



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112024-258493  
CG-DL-E-06112024-258493

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4441]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2024/कार्तिक 15, 1946

No. 4441]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2024/KARTIKA 15, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2024

का.आ. 4822(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि, लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि सीसा और जस्ता खनन उद्योग में लगी हुई सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 14 और 15 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी;

और, केन्द्रीय सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय सरकार भारत की अधिसूचना संख्या का.आ. 1943(अ), तारीख 7 मई, 2024 द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 9 मई, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग को लोक उपयोगिता सेवा का दर्जा छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीसा और जस्ता खनन उद्योग में लगी हुई सेवाओं को 9 नवंबर 2024 से छह महीने की और अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/01/2024-आईआर(पीएल)]

दीपिका कच्छल संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th November, 2024

**S.O. 4822(E).**—WHEREAS the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the Lead and Zinc Mining Industry, which are covered under items 14 and 15 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 9th May, 2024 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1943(E), dated the 7th May, 2024;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the industry engaged in the Lead and Zinc Mining Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 9th November, 2024.

[F. No. S-11017/01/2023-IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.